RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 080
दि. 22.12.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

नगर परिषद से नगर पंचायत तक महायुति की ऐतिहासिक विजय, महाराष्ट्र की सियासत में नया अध्याय

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने एक नई तस्वीर उकेर दी है। राज्य की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति ने ऐसा दबदबा बनाया है, जिसे पिछले 30–35 वर्षों में दुर्लभ माना जा रहा है। जनता के इस स्पष्ट जनादेश ने न केवल भाजपा को राज्य की नंबर एक पार्टी के रूप में स्थापित किया है, बल्कि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) को नंबर दो और महाविकास अघाड़ी को हाशिये पर ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा है कि ऐसा समर्थन उन्होंने दशकों में नहीं देखा।

तीन–चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुए इन चुनावों में मतगणना 21 दिसंबर 2025 को सुबह शुरू हुई और शाम तक तस्वीर लगभग साफ हो गई। 288 में से 215 से अधिक परिषदों पर महायुति ने कब्जा जमाया, जबकि महाविकास अघाड़ी महज 51 परिषदों तक सिमट गई। भाजपा अकेले 129 नगर परिषदों में महापौर पद जीतने में सफल रही और उसके 3,325 पार्षद निर्वाचित हुए। शिवसेना (शिंदे गुट) ने 51 महापौर और 695 पार्षदों के साथ खुद को राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 35 महापौर और 311 पार्षद जीते, वहीं कांग्रेस भी 35 महापौर पदों तक ही सीमित रह गई। उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट दोनों ही दो अंकों तक नहीं पहुंच सके, जिससे विपक्ष की स्थिति और कमजोर होती दिखी। क्षेत्रवार नतीजों पर नजर डालें तो विदर्भ में भाजपा ने 100 में से 58 परिषदों पर जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ साबित की, जबकि मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र में भी भाजपा सबसे आगे रही। कोंकण क्षेत्र में शिवसेना

(शिंदे गुट) ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए भाजपा को कड़ी टक्कर दी। इन नतीजों ने यह साफ कर दिया कि राज्य के शहरी और अर्ध-शहरी मतदाता बड़े पैमाने पर महायुति के विकास और स्थिरता के दावे से सहमत नजर आए। हालांकि राज्य स्तर पर भाजपा और महायुति की आंधी चली, लेकिन कुछ जिलों में तस्वीर अलग भी रही। नासिक जिले में भाजपा का तथाकथित 'संकटमोचक' दांव काम नहीं आया और शिवसेना (शिंदे गुट) ने 11 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर बाजी मार ली। कुंभ मेले की तैयारियों के बीच यह हार भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। त्र्यंबकेश्वर और इगतपुरी जैसे क्षेत्रों में एकनाथ शिंदे की रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर दिए गए वादों ने मतदाताओं को प्रभावित किया। अंबरनाथ में मुकाबला और भी दिलचस्प रहा। भारी तनाव, विवाद और सियासी जंग के बीच हुए चुनाव में नगराध्यक्ष पद पर भाजपा की तेजश्री करंजुले ने जीत दर्ज की, लेकिन पार्षदों के मोर्चे पर शिवसेना (शिंदे गुट) ने बढ़त बना ली। कांग्रेस ने भी यहां अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। बदलापुर में भाजपा ने शिवसेना के गढ़ में सेंध लगाते हुए बड़ी जीत हासिल की, जबकि पुणे जिले में अजित पवार की एनसीपी ने 'दादा का जलवा' दिखाते हुए अधिकांश नगर परिषदों में अध्यक्ष पद अपने नाम किए। कोंकण के मालवण में राणे परिवार की सियासी जंग ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा, जहां शिवसेना (शिंदे गुट) ने भाजपा को मात देकर सत्ता पर कब्जा जमाया। वहीं चंद्रपुर में कांग्रेस ने विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में शानदार वापसी करते हुए 11 में से 8 सीटें जीत लीं और यह संदेश दिया कि कुछ इलाकों में अब भी पार्टी की जड़ें मजबूत हैं। नांदेड़ के लोहा नगर परिषद में भाजपा का परिवारवाद वाला प्रयोग मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया, जहां एक ही परिवार के छह उम्मीदवारों की हार ने पार्टी को असहज कर दिया।

नतीजों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि जनता ने भाजपा और महायुति को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उन्होंने इसे 2017 से भी बड़ी जीत बताते हुए संगठन, सहयोगी दलों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना अब ठाणे तक सीमित नहीं रही, बल्कि चंद्रपुर से बांद्रा तक मजबूत हुई है और राज्य की नंबर दो पार्टी बनकर उभरी है। वहीं विपक्ष ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नतीजों को "मशीन की सेटिंग" करार दिया, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जनता ने विपक्ष के झूठे प्रचार को नकार दिया है।

स्थानीय निकाय चुनावों में मिली इस बड़ी जीत के बाद महायुति का अगला लक्ष्य अब 'मिशन मुंबई' है। जनवरी में होने वाले बीएमसी और अन्य नगर निगम चुनावों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन का आत्मविश्वास चरम पर है। इन नतीजों ने न केवल महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक दिशा तय की है, बल्कि आने वाले शहरी चुनावों के लिए भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।

घुसपैठ और वोटबैंक की राजनीति पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, असम की पहचान से समझौता नहीं करेगी भाजपा

(जीएनएस)। नम्रूप। असम के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए घुसपैठ और वोटबैंक की राजनीति को लेकर कड़े आरोप लगाए। नम्रूप में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया-यूरिया प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज भी देश और असम के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहती है और इसी कारण वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण यानी एसआईआर का विरोध कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट के लिए ऐतिहासिक है। नम्रूप और डिब्रूगढ़ जैसे क्षेत्रों को लंबे समय से जिस औद्योगिक विकास का इंतजार था, वह अब साकार हो रहा है। उन्होंने गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन और नम्रूप में उर्वरक परियोजना

की शुरुआत को असम की बदलती तस्वीर का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले नॉर्थ-ईस्ट को देश की मुख्यधारा से कटा हुआ माना जाता था, लेकिन अब यह क्षेत्र विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नम्रूप में बनने वाला आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल किसानों को समय पर और पर्याप्त उर्वरक मिलेगा, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार देगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के निर्माण में किसानों और युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यूरिया के लिए किसानों को लंबी-लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था और कालाबाजारी आम बात थी, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब चार लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वही पार्टी है जिसने वर्षों तक देश में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति के तहत घुसपैठियों को संरक्षण दिया और आज भी उन्हें बचाने के लिए वोटर लिस्ट शुद्धिकरण जैसे जरूरी कदमों का विरोध कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को न तो असम की पहचान की चिंता है और न ही यहां के लोगों के सम्मान की, उसकी राजनीति सिर्फ वोटबैंक तक सीमित है।

प्रधानमंत्री ने असम के लोगों को भरोसा दिलाया कि भाजपा राज्य की पहचान, संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि असम की धरती ने देश को हमेशा समृद्ध किया है और यहां की पहचान से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने लोगों से तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति को नकारने की अपील करते हुए कहा कि विकास, सुरक्षा और सम्मान ही असम और देश के उज्ज्वल भविष्य का रास्ता है।

विकसित भारत की दिशा में बड़ा बदलाव, मनरेगा की जगह VB–G RAM G कानून लागू, ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़

(जीएनएस)। नई दिल्ली। ग्रामीण भारत की रोजगार व्यवस्था में एक बड़े और निर्णायक बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल, 2025 यानी VB–G RAM G को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब औपचारिक रूप से कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से केंद्र सरकार के 'विकसित भारत 2047' विजन को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। सरकार इस नए कानून को 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है।

करीब दो दशक पहले शुरू हुई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा अब इतिहास बनने जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार, VB–G RAM G कानून मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण रोजगार को एक नए ढांचे और व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि बीते वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण

आय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई, लेकिन बदलते समय, बढ़ती आबादी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई जरूरतों को देखते हुए एक अधिक सशक्त और टिकाऊ कानून की आवश्यकता थी। इसी सोच के तहत यह नया कानून तैयार किया गया है।

VB–G RAM G कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को अब हर वित्त वर्ष में 125 दिनों का वैधानिक मजदूरी रोजगार मिलेगा, जो मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों की तुलना में 25 दिन अधिक है। सबसे अहम बात यह है कि यह रोजगार सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी। यानी अगर कोई पात्र ग्रामीण परिवार रोजगार की मांग करता है, तो सरकार को तय समयसीमा के भीतर काम उपलब्ध कराना ही होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा को और मजबूत आधार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

नए कानून में मजदूरी भुगतान को लेकर भी सख्त और स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। मजदूरों को अब साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित लाभार्थी को मुआवजा देना भी कानूनन जरूरी होगा। सरकार का दावा है कि इससे वर्षों से चली आ रही देरी की शिकायतों पर लगाम लगेगी और ग्रामीण मजदूरों का भरोसा व्यवस्था में मजबूत होगा।

इस विधेयक को संसद में पारित किए जाने के दौरान विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को खत्म कर महात्मा गांधी के नाम और उनके आदर्शों को कमजोर कर रही है। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक गांधी जी के नाम का राजनीतिक उपयोग किया, जबकि मौजूदा सरकार उनके विचारों को नए सिरे से मजबूत कर रही है। उनका कहना था कि यह कानून केवल नाम बदलने की कवायद नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने का प्रयास है।

सरकार के अनुसार VB–G RAM G कानून का दायरा सिर्फ मजदूरी रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, कृषि और गैर-कृषि रोजगार के बीच संतुलन, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी है। इससे गांवों में सड़क, जल संरक्षण, सिंचाई, हरित परियोजनाओं और आजीविका से जुड़े कार्यों को नई गति मिलने की संभावना है।

केंद्र सरकार इसे ग्रामीण भारत के लिए एक दूरगामी सुधार मान रही है। उसका दावा है कि यह कानून न केवल ग्रामीण बेरोजगारी को कम करेगा, बल्कि पलायन पर भी अंकुश लगाएगा और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेगा।

हिजाब विवाद पर नीतीश के साथ खड़े जीतनराम मांझी, बोले बेवजह राजनीति कर मुद्दे को दिया जा रहा सांप्रदायिक रंग

(जीएनएस)। गया। आयुष विभाग की महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़े विवाद पर बिहार की राजनीति गरमा गई है, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) के राष्ट्रीय संरक्षक जीतनराम मांझी खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में सामने आए हैं। गया में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मांझी ने कहा कि इस घटना को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है और कुछ लोग जानबूझकर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।

जीतनराम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी उम्र 74 वर्ष है और उनका सार्वजनिक जीवन दशकों का रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर ऐसी कोई बात किसी 22 साल के युवक से हुई होती तो उस पर सवाल उठाए जा सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता के हर शब्द और कदम को एक अभिभावक की भावना से देखना चाहिए। मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक पिता या संरक्षक की तरह महिला डॉक्टर को समझाने की कोशिश की, न कि किसी गलत मंशा से कोई टिप्पणी की।

मांझी ने यह भी कहा कि आयुष विभाग में ज्वाइन करने जा रही महिला डॉक्टर को पेशेवर दृष्टिकोण से समझाना किसी भी तरह गलत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई डॉक्टर मरीजों के सामने जाती है, तो उसकी पेशेवर छवि और व्यवहार भी मायने रखता है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री ने एक सामान्य सलाह दी तो उसे विवाद का रूप देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और तत्व इस मामले को जानबूझकर उछाल रहे हैं ताकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके। केंद्रीय मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि खुद संबंधित महिला डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री की मंशा पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है और वह अपना पदभार संभालने जा रही हैं।

अरावली पर संरक्षण पहले से ज्यादा मजबूत, खनन को लेकर फैलाया जा रहा भ्रमः भूपेंद्र यादव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद देशभर में उठे विवाद पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अरावली को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है और यह दावा पूरी तरह गलत है कि नई व्यवस्था से खनन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सच्चाई इसके ठीक उलट है और नई परिभाषा के तहत अरावली का संरक्षण पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है।

सुंदरबन टाइगर रिजर्व में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत रूपरेखा के अनुसार अरावली क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संरक्षित श्रेणी में रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि खनन को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, वे तथ्यहीन हैं और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पहले से ही रोक है और व्यापक प्रबंधन योजना लागू होने तक किसी भी प्रकार की नई अनुमति नहीं दी जाएगी।

सरकार के अनुसार, नई परिभाषा का उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला को कानूनी और प्रशासनिक रूप से स्पष्ट रूप देना है, ताकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्याख्याओं के कारण जो खामियां पैदा हो रही थीं, उन्हें दूर किया जा सके। भूपेंद्र यादव ने बताया कि 100 मीटर का मानदंड सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी संबंधित राज्यों में लागू किया गया है, ताकि पहाड़ियों के आधार तक खनन के दुरुपयोग को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यह मानदंड किसी भी तरह से संरक्षण को कमजोर नहीं करता, बल्कि मानकीकरण के जरिए निगरानी को और प्रभावी बनाता है।

पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम

कोर्ट ने मई 2024 में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्रालय के सचिव ने की थी और इसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति की जांच में यह सामने आया कि वर्ष 2006 से केवल राजस्थान में अरावली की औपचारिक परिभाषा लागू है, जबकि अन्य राज्यों में स्पष्ट मानक नहीं थे। इसी अनुभव के आधार पर सभी राज्यों ने एक समान मॉडल अपनाने पर सहमति जताई, ताकि संरक्षण व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।

नई व्यवस्था में सुरक्षा के कई अतिरिक्त प्रावधान भी जोड़े गए हैं। इसके तहत 500 मीटर के भीतर स्थित पहाड़ियों को एक ही पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा, ताकि खनन के नाम पर पहाड़ी तंत्र को टुकड़ों में बांटकर नुकसान न पहुंचाया जा सके। खनन से पहले सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों पर अनिवार्य मैपिंग, कोर और इनवायोलेट क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान जैसे प्रावधान किए गए हैं, जहां किसी भी स्थिति में खनन की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 100 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में खनन की अनुमति देने का दावा पूरी तरह गलत है और प्रतिबंध केवल चोटी या ढलान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र पर लागू रहेगा।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में अरावली क्षेत्र का महज 0.19 फीसदी हिस्सा ही कानूनी रूप से खनन के दायरे में आता है, जबकि दिल्ली के अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं है। सरकार का कहना है कि अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा आज भी अवैध और अनियंत्रित खनन है, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत नई परिभाषा। इसी वजह से निगरानी और प्रवर्तन को और सख्त करने की तैयारी की जा रही है।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इमेजरी और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे उपायों से अरावली क्षेत्र की निगरानी मजबूत की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर चल रही है और अरावली जैसी ऐतिहासिक और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

संपादकीय

आइसिस की जड़ों को भारत में ढूंढ़ने की ज़रूरत

सीरिया के शासन प्रमुख अपने देशवासियों के साथ गर्व महसूस कर रहे हैं। वजह, अहमद अल-अहमद हैं। सीरियाई मूल का अहमद अल-अहमद, सिडनी के सदरलैंड शायर में एक दुकान चलाता है। बौंडी बीच पर उसके कारनामों ने उसे दुनियाभर में एक शांत दुकानदार से बहादुरी के प्रतीक में बदल दिया। हथियारबंद हमलावरों का सामना करने की कोशिश में अल-अहमद को दो गोलियां लगीं। उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में तत्काल ले जाया गया, वहां उनकी सर्जरी हुई, और अब वो ठीक हैं। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, क्रिस मिन्स ने उनसे मिलने के बाद फेसबुक पर लिखा—'अल-अहमद की अविश्वसनीय बहादुरी ने निस्संदेह अनगिनत जानें बचाईं, जब उन्होंने अपनी जान का रिस्क लेकर एक आतंकवादी को निहत्था किया। ये है असली हीरो।' इस हमले की विश्वव्यापी निंदा की गई है। अल-अहमद ने सीरिया का सिर ऊंचा किया। भारत शर्मिंदा, और सन्नाटे में है। वजह हमलावरों का हैदराबाद कनेक्शन है। बौंडी बीच हमले में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वालों में से एक बंदूकधारी भी शामिल है, जिसकी पहचान पुलिस ने 50 वर्षीय साजिद अकरम के रूप में की है। उस शख्स का 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम, गोली लगने के बाद अस्पताल में गंभीर हालत में बताया जा रहा है। साजिद अकरम हैदराबाद का था, और उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट धारक था। बौंडी बीच शूटर साजिद अकरम 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। उसके रिश्तेदारों ने बताया, 'साजिद अकरम 2001 में अपनी यूरोपीय मूल की पत्नी को एक निकाह समारोह के लिए हैदराबाद लाया था, और अपने बेटे नवीद अकरम को 2004-05 में अपने माता-पिता से मिलवाने के लिए लाया था।' ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने जानकारी दी, कि दोनों जने पिछले महीने फिलीपींस गए थे, पिता भारतीय पासपोर्ट पर, और बेटा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर। फिलीपींस के अधिकारियों ने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद जांच के दायरे में है, और यह कहना पक्का नहीं है कि वे किसी आतंकवादी समूह से जुड़े थे, या उन्हें उस देश में ट्रेनिंग मिली थी। मंगलवार को अपने बयान में, तेलंगाना पुलिस ने कहा कि 1998 में ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद से साजिद अकरम छह बार भारत आया था, मुख्य रूप से पारिवारिक कारणों से। बयान में यह भी कहा गया, कि भारत छोड़ने से पहले उसका कोई 'बुरा रिकॉर्ड' नहीं था।

हमलावरों ने बोंडी बीच पर हाहाकारी हमले से पहले फिलीपींस में एक महीना बिताया था। फिलीपींस में ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन ने कन्फर्म किया है, कि बाप-बेटे नरसंहार से पहले उनके देश में 28 दिन रुके थे। इमिग्रेशन प्रवक्ता डाना सैंडोवल ने बुधवार को कहा, कि 50 साल का साजिद अकरम और उसका बेटा 24 साल का नवीद अकरम 1 नवंबर, 2025 को निनॉय एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने दावो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी। 28 नवंबर को बाप-बेटे, दावो सिटी से मनीला के लिए निकले, और फिलीपीन एयरलाइंस की फ्लाइट 'पीआर 212' से वापस सिडनी चले गए। फिलीपींस का दावो, मिंडानाओ के दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा शहर है, जहां मुस्लिम विद्रोही लंबे समय से एक स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2017 में, आइसिस लड़ाकों ने मिंडानाओ में मारावी शहर को पांच महीने तक घेरे रखा, जिससे फिलीपींस सरकार को एक पूर्ण युद्ध शुरू करना पड़ा, जिसमें आइसिस के प्रमुख नेताओं को मार गिराया गया, और लड़ाकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, कैथोलिक बहुल देश फिलीपींस में सैकड़ों इस्लामिक स्टेट के लड़ाके अभी भी मौजूद हैं। आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय आका मिंडानाओ में गरीबी, अंतर्विरोध व सरकारी दमनचक्र का फायदा उठाकर भर्ती अभियान जारी रखे हुए हैं। विशेषज्ञ बताते हैं, दहशतगर्दों के ऑपरेटर्स ने अपनी रणनीति बदल ली है। वे छोटे-छोटे गुटों में बंट गए हैं, लेकिन फिर भी इस्लामिक स्टेट के प्रति वफादार हैं। उन्होंने पुलिस बलों और ईसाई पूजा स्थलों को निशाना बनाना जारी रखा है। 2023 में, इस्लामिक आतंकवादियों ने मारावी में मिंडानाओ स्टेट यूनिवर्सिटी में एक कैथोलिक मास के दौरान एक विस्फोटक डिवाइस से धमाका किया, जिसमें चार लोग मारे गए, और दर्जनों घायल हो गए। फिलीपींस में आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ रोमेल बानलाओई ने कहा, कि मारावी घेराबंदी के बाद इस क्षेत्र में उग्रवाद आंदोलनों में बदलाव आया है। बानलाओई ने कहा, 'पहले, इनका ध्यान एक इस्लामिक राज्य बनाने पर था।

विश्व की दिशा परिवर्तन का वर्ष

> स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट ने ट्रंप के इस रवैये को अमेरिका की 'सभ्यतागत आत्महत्या' की संज्ञा दी है। उदार लोकतंत्र, खुली स्पर्धा और नियमबद्ध व्यवस्था जैसे आदर्शों को ताक पर रखकर ट्रंप तीन महाशक्तियों के दबदबे वाली दुनिया बनाने की राह पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के किसी मंच पर अब जुबानी जमाखर्च के सिवा इन तीनों की आमराय के बिना कुछ हो पाने की संभावना कम ही दिखती है। ऐसे में असली चुनौती यूरोप और भारत के सामने है कि कैसे अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर होकर अपना दबदबा बढ़ाएं और कारोबार फैलाएं।

विश्व आर्थिक मंच, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, राजनयिक और विश्लेषक वर्ष 2025 को दुनिया की दिशा बदलने वाले वर्ष के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाटकीय टैरिफ नीति, वैश्विक समीकरणों और व्यवस्थागत नियमों में हुई ऐसी उथल-पुथल है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही विश्व व्यवस्था में पहले कभी नहीं देखी गई।

वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार बढ़कर 40 गुना से अधिक हो गया था जिसके कारण दुनिया के एक अरब से अधिक लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकल सके, लेकिन इस दौर में उद्योग-धंधे अमेरिका और यूरोप छोड़कर एशियाई देशों में चले गए, जहां कच्चा माल और मज़दूरी सस्ती थी। इससे अमेरिका और यूरोप में कामगार बेरोजगार हुए और व्यापार घाटे भी बढ़े। ट्रंप इसी प्रक्रिया को पलटने के वादे पर चुनाव जीते थे। इसलिए उन्होंने सत्ता संभालते ही कुछ देशों पर भारी टैरिफ लगाने के साथ-साथ छोटे-बड़े सभी देशों पर टैरिफ लगा दिए। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाया गया, ताकि विश्व व्यापार संगठन में चुनौती न दी जा सके। पिछले 70 वर्षों से मुक्त व्यापार की वकालत करते आ रहे देश ने 30 वर्ष लंबी गैट वार्ताओं के बाद बनी विश्व व्यापार की व्यवस्था को एक एलान से ध्वस्त कर दिया।

ट्रंप के टैरिफ युद्ध का प्रमुख निशाना चीन था, परंतु उसने अपने दुर्लभ खनिजों और

औद्योगिक चुंबकों के ब्रह्मास्त्र से अपना बचाव कर लिया। भारत और ब्राजील इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों पर सर्वाधिक ऊंचे 50 प्रतिशत टैरिफ लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूस पर युद्धविराम का दबाव डालने के लिए ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीदना बंद करने का दबाव डाल रहे हैं, जिसे वे दोस्त कहते हैं। जबकि रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार और प्रतिद्वंद्वी चीन से कुछ नहीं कहते। नाटो में अपने सहयोगी तुर्किये से कुछ नहीं कहते। अपने दोस्त हंगरी के नेता ओर्बान को खरीदने की छूट दे रहे हैं और खुद रूस से परमाणु ईंधन की खरीदारी जारी है। ट्रंप की अबूझ नीतियों के कारण यह साल 25 वर्षों से घनिष्ठ होते आ रहे भारत-अमेरिका रिश्तों पर संदेह और अनिश्चितता के साए का साल रहा।

इस नियमहीन धौंस की कूटनीति ने चीन, रूस और ब्राजील जैसी ब्रिक्स शक्तियों को डालर के बिना व्यापार करने के उपाय खोजने पर विवश किया। ये देश अब अपना अधिकांश व्यापार अपनी मुद्राओं में करने लगे हैं। रूस और चीन करीब 250 अरब डालर के व्यापार का 99.1 प्रतिशत अपनी मुद्राओं में करते हैं। भारत-रूस भी अपने व्यापार का 96 प्रतिशत अपनी मुद्राओं में करते हैं। चीन और ब्राजील भी आपसी व्यापार अपनी मुद्राओं में करने लगे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए डालर मुक्त व्यापार नया नहीं है, पर ट्रंप की मनमानी और धौंस ने इसे नई गति दी है।

ट्रंप की नीतियों की अस्थिरता और अप्रत्याशितता ने सामरिक समीकरणों को भी उलटा-पलटा है। यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्तों की बुनियाद सदियों पुरानी है। दूसरे महायुद्ध में यूरोप के जर्जर और कंगाल हो जाने के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सामरिक और आर्थिक शक्ति बनकर उभरा था। इसलिए उसने अपने नेतृत्व में विश्व के लिए एक नई नियमबद्ध व्यवस्था बनाई जो उसके उदार लोकतंत्र, खुली स्पर्धा वाली आर्थिकी और कानून व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित थी।

यूरोप उसका सामरिक साथी और वैचारिक प्रयोगशाला बना। यूरोप ने शीतयुद्ध के दौरान साम्यवादी एकदलीय तानाशाही के फैलाव को रोके रखा। सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए पूर्वी यूरोप के देशों ने अमेरिका और यूरोप की व्यवस्था को केवल तेज आर्थिक विकास के लिए ही नहीं अपनाया था। उन्हें साम्यवादी तानाशाही से अपना अस्तित्व भी बचाना था और उम्मीद थी कि यूरोप और अमेरिका उनकी रक्षा करेंगे। ट्रंप यूक्रेन के बचाव की जगह पुतिन को खुश रखने के लिए जिस तरह उसकी जमीन और सुरक्षा का सौदा करने में लगे हैं, उसने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है।

यूरोप को सबसे बड़ा धक्का ट्रंप की नई सुरक्षा नीति में पुतिन के हमले और तानाशाही की आलोचना की जगह अपनी आलोचना को पढ़कर लगा है। अमेरिकी सुरक्षा नीति कहती है कि लचर नीतियों के कारण यूरोप के कुछ देशों में कुछ ही दशकों के भीतर यूरोपीय सभ्यता लुप्त हो जाएगी, क्योंकि गैर-यूरोपीय बहुसंख्यक बन जाएंगे। इसलिए वह यूरोप में राष्ट्रवादी पार्टियों को सत्ता में देखना चाहती है। स्पष्ट है कि ट्रंप यूरोप को अब एक बोझ के सिवा कुछ नहीं मानते। दूसरी तरफ पुतिन का स्वागत वे महाशक्ति की तरह तालियां बजाकर करते हैं। चीनी राष्ट्रपति के साथ होने वाली शिखर बैठक को जी-2 की संज्ञा देकर वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि चीन अब बराबर की महाशक्ति है।

स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट ने ट्रंप के इस रवैये को अमेरिका की 'सभ्यतागत आत्महत्या' की संज्ञा दी है। उदार लोकतंत्र, खुली स्पर्धा और नियमबद्ध व्यवस्था जैसे आदर्शों को ताक पर रखकर ट्रंप तीन महाशक्तियों के दबदबे वाली दुनिया बनाने की राह पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के किसी मंच पर अब जुबानी जमाखर्च के सिवा इन तीनों की आमराय के बिना कुछ हो पाने की संभावना कम ही दिखती है। ऐसे में असली चुनौती यूरोप और भारत के सामने है कि कैसे अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर होकर अपना दबदबा बढ़ाएं और कारोबार फैलाएं। इसमें कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि दुनिया तिकोना रूप लेती है तो समर्थन-शक्ति के लिए कई छोटे देश साथ आना चाहेंगे। तीन या अधिक धुरियों में बंटी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और जिहादी आतंक की रोकथाम जैसी वैश्विक चुनौतियों पर अब क्षेत्रीय सहयोग जुटाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष का सबसे बड़ा दिशा परिवर्तन एआइ या यंत्रमेधा का आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र में सक्रिय हो जाना है। 30 वर्ष पुरानी सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के बाद यह उससे भी बड़ी क्रांति है, जो खोज से लेकर निर्माण और उपभोग तक उत्पादन के हर पहलू को और कामकाज को प्रभावित करेगी।

प्रेरणा

महानता की घोषणा और तालियों का अकाल

कहते हैं महान लोग अपने काम से पहचाने जाते हैं, लेकिन आज के समय में महानता की पहचान का पैमाना थोड़ा बदल गया है। अब काम करना उतना ज़रूरी नहीं, जितना उसका ढिंढोरा पीटना ज़रूरी हो गया है। हमारे मोहल्ले में रहने वाले अस्सी बरस के एक बुज़ुर्ग इसी बदले हुए दौर के सबसे सशक्त उदाहरण हैं। वे न सिर्फ़ अपने आपको शानदार, जानदार, रोबदार और ज़ोरदार मानते हैं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ यह भी मानते हैं कि दुनिया को भी यही मान लेना चाहिए।

कुछ समय पहले उन्होंने बड़े गर्व के साथ ऐलान किया कि उन्होंने राम और श्याम की बचपन से चली आ रही लड़ाई बंद करवा दी है। बात बड़ी थी, घोषणा उससे भी बड़ी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि न राम ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को स्वीकार किया और न श्याम ने। दोनों पहले की तरह लड़ते रहे और उल्टा अंकल के पास आकर यह कह बैठे कि झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलती। इस पर अंकल ने ज़ोरदार अंग्रेज़ी और उससे भी ज़ोरदार आत्मविश्वास के साथ समझाया कि दुआओं और शुभकामनाओं के दम पर उन्होंने सौ साल पुराना झगड़ा सेटल करवा दिया है और अब ये दोनों लड़ने का नाटक कर रहे हैं।

अंकल का तर्क बड़ा आध्यात्मिक था। उनका मानना है कि जैसे बददुआएँ असर करती हैं, वैसे ही दुआएँ भी असर करती हैं, बस दुआ देने वाला व्यक्ति शानदार, जानदार, रोबदार और ज़ोरदार होना चाहिए। उनके भीतर का आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि सच्चाई कुछ और ही कह रही है। वे मन ही मन ठहाका लगाते हुए सोचते रहे कि कोई यह नहीं मानेगा कि कभी इसी लड़ाई को हवा देने में उनका भी योगदान रहा था—कभी उकसावे, कभी गालियों की आपूर्ति, कभी स्थानीय संसाधनों जैसे डंडे, ईंट-पत्थर और हाथापाई की व्यवस्थाएँ। आखिरकार, समाज की सामूहिक स्मृति भी बड़ी सुविधाजनक होती है; उसे वही याद रहता है, जो बार-बार बताया जाए।

समय बीतने के साथ अंकल की उपलब्धियों की सूची लंबी होती गई। राम और श्याम के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि डेढ़ दर्जन छोटे-बड़े मोहल्लों के झगड़े सुलझा दिए हैं। यह अलग बात है कि उन झगड़ों में शामिल लोग अब भी पहले की तरह उलझे हुए हैं, लेकिन अंकल की घोषणा में कहीं कोई कमी नहीं। समस्या बस इतनी है कि लोग उनके इन महान कार्यों की सराहना नहीं कर रहे। न ताली बजा रहे हैं, न जयकार कर रहे हैं। सब अपने-अपने मोबाइल फोन में डूबे हुए हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के आभासी बाथटब में लेटे हुए अपनी-अपनी महानता का साबुन लगा रहे हैं। अंकल को इस बात का गहरा दुख है कि दूसरों की तारीफ़ करने और सुनने का चलन लगभग समाप्त हो गया है। उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति युद्ध रुकवाने, लड़ाई खत्म करवाने और मानवता के नाम पर बड़े-बड़े दावे कर रहा हो, तो उसे सम्मान, पुरस्कार और कम से कम सार्वजनिक प्रशंसा तो मिलनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो दोष उस व्यक्ति में नहीं, बल्कि समाज की कृतघ्नता में है।

इसी चिंतन से एक नया जीवन-दर्शन जन्म लेता है—अपनी तारीफ़ खुद करो। इंतज़ार मत करो कि कोई और करेगा, क्योंकि आज के दौर में सब अपनी-अपनी तारीफ़ में इतने व्यस्त हैं कि दूसरों के लिए समय ही नहीं बचा। अंकल का यह दर्शन बड़ा व्यावहारिक है। इससे आत्मसंतोष भी मिलता है और अस्वीकार किए जाने का दर्द भी कम होता है।

पुरस्कार देने वाली संस्थाओं पर भी अंकल का भरोसा अब डगमगा चुका है। उन्हें लगता है कि चयन करने वाले लोग सही लोगों को पहचान ही नहीं पा रहे। इतनी बड़ी-बड़ी उपलब्धियों के बावजूद अगर किसी को सम्मान न मिले, तो यह व्यवस्था की विफलता है। लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हैं। उनका विश्वास अडिग है कि महानता किसी प्रमाणपत्र या ट्रॉफी की मोहताज नहीं होती।

आखिर में यही निष्कर्ष निकलता है कि समय चाहे जितना खराब क्यों न हो, अच्छे काम करने का दावा करने वाले लोग अपना काम—या कम से कम उसकी घोषणा—करते रहेंगे। तारीफ़ मिले या न मिले, तालियाँ बजें या न बजें, महानता का तमगा वे खुद ही अपने सीने पर टांक लेंगे। क्योंकि इस दौर में सबसे सुरक्षित और स्थायी सम्मान वही है, जो इंसान खुद को दे सके।

सूरा सो पहचानिये, जो लरै दीन के हेत

करीब 320 वर्ष पहले दिसंबर की भीषण ठंड में पंजाब में शौर्य और धर्मयुद्ध के इतिहास का अप्रतिम अध्याय लिखा जा रहा था। यह अध्याय है गुरु गोबिंद सिंह के चारों बेटों और उनकी वृद्ध मां के आत्म-बलिदान का। यह विश्व इतिहास की एक विरल घटना है कि धर्म बदलने की बात न मानने के लिए नौ और छह साल के दो बच्चे शासक के आदेश से दीवार में जीवित चुनवा दिए गए हों। हाथ बंधे, कैद में नंगी तलवारों से घिरे गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों छोटे बेटे मुगल सत्ता के एक शक्तिशाली प्रतिनिधि से बकायदा जंग लड़ रहे थे। अपनी तेजस्विता और संकल्प बल से, यही उनके पास था।

दिसंबर, 1704 के उत्तरार्ध में एक रात जब गुरु गोबिंद सिंह ने सुरक्षित जाने देने की बादशाह औरंगजेब की कुरान और पहाड़ी राजाओं की गाय की शपथ पर आनंदपुर साहिब छोड़ा तो वही हुआ, जिसका उन्हें अंदेशा था। मुगल और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना ने पीछे से उन पर हमला बोल दिया। धोखा देकर किए गए इस हमले की आपाधापी में कई सिख सैनिक मारे गए और गुरु गोबिंद सिंह जी का कीमती सामान, पोथियां, 'विद्यासागर' आदि रचनाएं व संस्कृत से अनुवाद कराया गया साहित्य वगैरह नदी में नष्ट हो गए। गुरु परिवार भी बिखर गया।

इस धोखे और आपाधापी के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी रास्ता भटक गईं और उनके साथ गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे बेटे नौ साल के बाबा जोरावर सिंह और छह साल के बाबा फतेह सिंह गिरफ्तार कर सरहिंद (जिला फतेहगढ़ साहिब) ले जाए गए। सरहिंद के फौजदार नवाब वजीर खां ने उन्हें नदी के किनारे सुनसान पड़े और चारों ओर से खुले एक ऊंचे बुर्ज में रखवाया। भीषण ठंड में पुआल में बैठकर ठिठुरते हुए दोनों बच्चों और माता गुजरी ने रात काटी।

23 दिसंबर, 1705 को सुबह माता गुजरी को वहीं छोड़ सशस्त्र सिपाही दोनों लड़कों को फौजदार के दरबार ले गए। दो दिन तक यह क्रम चला।

नवाब ने बच्चों का मनोबल तोड़ने को यह भी कहा कि तुम्हारे बाप-भाई वगैरह सब मार दिए गए हैं, अब तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगे। हमारी बात मान लो तो ऐश करोगे। समझाया, प्रलोभन दिया और क्रूरतापूर्वक मार दिए जाने को डराया। कहा- इस्लाम अपना लो, रिहा कर दिए जाओगे। बच्चे तनकर कहते- मार दो, मगर धर्म नहीं छोड़ेंगे। नवाब भी हैरान-परेशान था, उसने ऐसे निडर और संकल्प के धनी लड़के नहीं देखे थे। वे ऐसे कड़क जवाब देते रहे कि उसने झल्लाकर तीसरे दिन उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा देने का आदेश दे दिया। ये बच्चे कई रातों के जगे और कई दिनों के भूखे थे, तब भी। दोनों बच्चे अडिग थे, उनके चेहरे पर शिकन नहीं। दीवार चुन दी गई और दम घुटने से दोनों की सांसें थम गईं। 'सूरज प्रकाश' और 'गुरबिलास' के अनुसार दोनों के सिर कलम किए गए। कहा जाता है कि दीवार गिर गई तो बाद में जल्लाद ने उनके सिर काटे।

उधर 22 दिसंबर, 1704 को चमकौर में हुए युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनो बड़े बेटे 18 साल के साहिबजादा अजीत सिंह, 14 वर्षीय बाबा जुझार सिंह और 37 सिख वीरगति को प्राप्त हुए। यह विश्व इतिहास का अनूठा युद्ध है, जिसमें करीब एक लाख की मुगल सेना भीषण युद्ध के बाद भी कच्ची गढ़ी में गुरु गोबिंद सिंह जी तक पहुंच नहीं पाई। गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ उनके दो बड़े बेटे और मात्र चालीस सिख थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़े उत्साह से अपने पुत्रों को गले लगा कर और पीठ थपथपा कर चार सिखों के जत्थे के साथ युद्ध मैदान में जाने को भेजा और बड़े बेटे के बाद छोटे बेटे का बलिदान भी देखा!

अपने पितामह की तरह दोनों बालकों नौ साल के बाबा जोरावर सिंह और छह साल के बाबा फतेह सिंह ने प्राण तो दे दिए, लेकिन धर्म नहीं दिया। ये दोनों गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे थे, वही गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हें इस घटना के ढाई-तीन साल बाद औरंगजेब के उत्तराधिकारी और बड़े बेटे बहादुर शाह ने 'हिंद का पीर' यानी भारत का संत कहा। अपने दोनों पौत्र, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को जीवित दीवार में चुनवा दिए जाने का सदमा 81 वर्षीया दादी माता गुजरी बर्दाश्त नहीं कर सकीं और यह खबर सुनने पर उसी दिन उनके प्राण-पखेरू उड़ गए। वह विश्व इतिहास का अकेला ऐसा नाम हैं, जो आत्म बलिदानी की पत्नी थीं, मां थीं, दादी थीं और स्वयं भी सिख सिद्धांतों को लेकर बलिदान हुईं।

अभियान

भोलेनाथ की भक्ति से जीवन में शांति, शक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति का दिव्य मार्ग

हिंदू सनातन परंपरा में सोमवार का दिन केवल सप्ताह का एक साधारण दिन नहीं, बल्कि आस्था, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर वह पावन अवसर है, जब सृष्टि के संहारक और पालनकर्ता भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों और लोकमान्यताओं में भगवान शिव को सबसे सरल, करुणामय और शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता माना गया है। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष कहा गया है। ऐसा विश्वास है कि जहां अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान, सामग्री और विधि-विधान की आवश्यकता होती है, वहीं भगवान शिव केवल एक लोटा जल, सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं।

सोमवार के दिन शिव भक्ति का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन चंद्रमा से जुड़ा हुआ माना जाता है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। ऐसे में सोमवार को शिव आराधना करने से मन की चंचलता, तनाव, भय और अस्थिरता शांत होती है। यही कारण है कि जिन लोगों के जीवन में मानसिक अशांति, पारिवारिक तनाव या निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बनी रहती है, उनके लिए सोमवार की शिव उपासना विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। विशेषकर महिलाएं और अविवाहित कन्याएं इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव से सुखी वैवाहिक जीवन, योग्य जीवनसाथी और पारिवारिक स्थिरता की कामना करती हैं।

मान्यताओं के अनुसार, सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान-ध्यान करके शुद्ध मन और शरीर के साथ भगवान शिव का स्मरण करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। स्वच्छता और पवित्रता शिव भक्ति का मूल आधार मानी गई है। पूजा के समय हल्के और शुभ रंगों के वस्त्र धारण करना जैसे सफेद, पीला, हरा, लाल या आसमानी रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इन रंगों को शांति, सादगी और सात्त्विकता का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय हैं।

शिव पूजा में अक्षत अर्थात साबुत चावल का विशेष महत्व है। माना जाता है कि टूटे या खंडित चावल पूजा में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा अखंड चावल ही अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही सोमवार के दिन दूध, दही, सफेद वस्त्र और शक्कर का दान करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। धार्मिक विश्वास है कि इस प्रकार का दान करने से न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि जीवन में आर्थिक स्थिरता, मानसिक संतुलन और पारिवारिक सुख भी बढ़ता है।

सोमवार को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने की भी विशेष महिमा बताई गई है। यह स्तोत्र नकारात्मक शक्तियों, भय, रोग और आकस्मिक संकटों से रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ शिव रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है और जीवन की कठिन परिस्थितियां धीरे-धीरे सरल होने लगती हैं। संध्या के समय कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करने की परंपरा भी प्रचलित है। यह उपाय विशेष रूप से ग्रह दोषों, मानसिक बेचैनी और जीवन में रुकावटों को दूर करने वाला माना गया है।

वास्तव में सोमवार का महत्व केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन आत्मचिंतन, संयम और आंतरिक शुद्धि का अवसर भी प्रदान करता है। भगवान शिव की भक्ति यह सिखाती है कि सादगी में ही सच्ची शक्ति है और अहंकार का त्याग ही सच्चा वैराग्य है। जब भक्त बिना किसी दिखावे के, केवल सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है, तो शिव स्वयं उसके जीवन की कठिनाइयों को हर लेते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है—यदि जीवन में कोई मार्ग दिखाई न दे, तो सोमवार के दिन भोलेनाथ के चरणों में शीश झुका दीजिए, शांति, समाधान और सफलता का मार्ग स्वयं खुलने लगेगा।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

अटल नेतृत्व, अविरत विकास

गुजरात में सुशासन से स्टार्टअप्स को मिली नई ऊँचाई : SSIP 2.0 तथा i-Hub बने गेम चेंजर

- स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 : पिछले 4 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 1,543 स्टार्टअप्स को मिली सहायता
- i-Hub के माध्यम से राज्य के लगभग 620 स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन तथा सहायता मिली
- स्टार्टअप क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण : WEstart पहल अंतर्गत 196 महिला-संचालित स्टार्टअप्स को सहायता
- i-Hub में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा राज्य में लगभग 1,400 कुशल रोजगार का सृजन, इन स्टार्टअप्स की कुल मार्केट वैल्यू 3,500 करोड़ रुपए से भी अधिक
- गुजरात सरकार की ओर से 15 लाख रुपए के अनुदान की सहायता से मनन बैटरीवाला ने स्थापित की 'कीपसेक ऑटोमेशन' कंपनी

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि नवीन विचारों, टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशन्स तथा युवा उद्यमियों की शक्ति देश के सर्वांगीण विकास का आधार हैं और विकसित भारत@2047 के निर्माण में स्टार्टअप तथा इनोवेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस बात को आत्मसात करते हुए राज्य में स्टार्टअप को व्यापक प्रोत्साहन दिया है और राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 (SSIP 2.0) जैसी पहल के जरिये उद्यमिता क्षेत्र में सुशासन का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज गुजरात उद्यमिता के केन्द्र के रूप में उभरा है और लगातार चौथी बार स्टार्टअप रैंकिंग में अग्रसर बना है। इतना ही नहीं; केन्द्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में गुजरात देश में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है और राज्य में अनुमानित 16,700 स्टार्टअप कार्यरत हैं। गुजरात में उद्यमिता को प्रोत्साहन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "युवा अपना बिजनेस शुरू करें और अन्य लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनें; यह क्षमता स्टार्टअप में है। गुजरात ने एक इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें WEstart तथा SSIP जैसे कार्यक्रम महिला उद्यमियों को सशक्त बनाते हैं।"

गुजरात स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (i-Hub) द्वारा लगभग 620 स्टार्टअप्स को सीधी सहायता मिली

स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी (SSIP) अंतर्गत गठित गुजरात स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (i-Hub) आज राज्य के इनोवेशन इकोसिस्टम का प्रमुख केन्द्र बन गया है। 5 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा i-Hub के नए भव्य कैम्पस का लोकार्पण किया गया था। i-Hub राज्य में इनोवेशन तथा एंटरप्रिन्योरशिप के लिए कार्यरत सबसे बड़ी सुविधा है; जहाँ सिंगल विंडो सपोर्ट के माध्यम से कानूनी, वित्तीय, तकनीकी एवं योजना संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है। यह सुविधा प्रारंभिक चरण के इनोवेटर्स तथा स्टार्टअप्स को उनके विचारों को सफल उद्योगों के रूप में विकसित करने में सहायता करती है। i-Hub का नया कैम्पस लगभग 1.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है, जो एक साथ लगभग 500 स्टार्टअप्स का समावेश कर सकता है। i-Hub द्वारा अब तक 620 स्टार्टअप्स को सीधी सहायता दी गई है और स्टार्टअप सृजन सीड सपोर्ट योजना अंतर्गत 402 स्टार्टअप्स को 23 करोड़ रुपए से अधिक की

SSIP 2.0 अंतर्गत पिछले 4 वर्ष में 1,543 स्टार्टअप को राज्य सरकार ने दी सहायता

उल्लेखनीय है कि SSIP 2.0 अंतर्गत कुल पाँच वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया जाता है। इसमें से 30 करड़ रुपए तकनीकी शिक्षा के लिए, 12 करोड़ रुपए i-Hub के लिए, 10 करोड़ उच्च शिक्षा के लिए और 8 करोड़ रुपए स्कूल के लिए आवंटित किए जाते हैं। SSIP 2.0 अंतर्गत 5,684 इनोवेशन को राज्य की 339 संस्थाओं के माध्यम से PoC/प्रोटोटाइप बनाने और 2,296 IPR फाइल करने के लिए समर्थन दिया गया तथा PoC/फंड सपोर्ट अंतर्गत 32.38 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई है, तो पिछले 4 वर्ष में 1,543 स्टार्टअप्स को SSIP 2.0 अंतर्गत राज्य सरकार की सहायता प्राप्त हुई है।

गुजरात सरकार की ओर से 15 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर मनन बैटरीवाला बने सफल उद्यमी

i-Hub की सहायता से 'कीपसेक ऑटोमेशन' नामक बड़ी कंपनी स्थापित करने वाले श्री मनन बैटरीवाला कहते हैं, "मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत एक फ्रीलांसर के रूप में की थी। उसमें से जब हमने एक कंपनी स्थापित करने का विचार किया, तब i-Hub ने हमें मार्गदर्शन दिया कि कंपनी किस तरह बनाई जाए, उसे आगे किस तरह ले जाया जाए। i-Hub ने कम्प्लायंस या लीगल किसी भी प्रकार की मदद के लिए भी सपोर्ट किया। इसके अतिरिक्त; i-Hub सेंटर की सहायता से हम कंपनी की पहचान स्थापित कर सके और हमने एग्जीबिशन मंच भी प्राप्त किया। आज हमारी कंपनी में 37 लोग काम कर रहे हैं। गुजरात सरकार की ओर से हमें कुल 15 लाख रुपए का अनुदान मिला है। इस सपोर्ट के कारण आज मैं एक सफल उद्यमी बना हूँ।"

गुजरात का मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम : SSIP 2.0 अंतर्गत विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक के विद्यार्थियों को मिलती है सर्वग्राही मेंटरशिप

युवाओं को इनोवेशन के लिए सक्षम आधार उपलब्ध हो; इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पाँच वर्ष (2022-2027) के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी (SSIP 2.0) घोषित की है। इस पॉलिसी के तहत विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक के विद्यार्थियों को सृजनशीलता के पंख मिलें; इसके लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

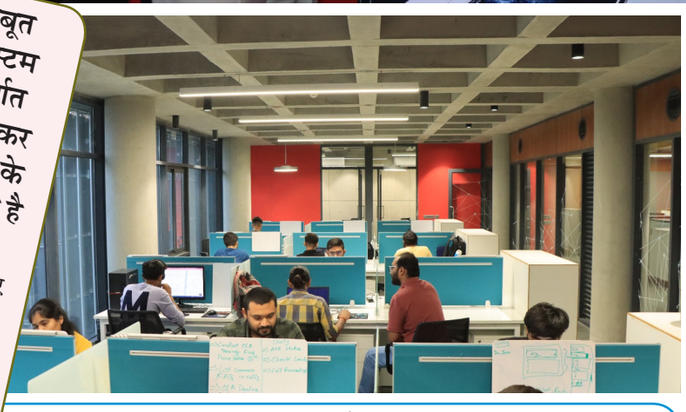

i-Hub के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा 1,400 कुशल रोजगार का सृजन हुआ

i-Hub के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा राज्य में लगभग 1,400 कुशल रोजगार का सृजन हुआ है, जबकि इन स्टार्टअप्स की कुल मार्केट वैल्यू लगभग 3,569 करोड़ रुपए तक पहुँची है। i-Hub के जरिये स्टार्टअप्स को विभिन्न वेंचर फंड्स द्वारा 416 करोड़ रुपए से अधिक का निजी फंड उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ; i-Hub ने 20 से अधिक जिलों में हब-एंड-स्पोक मॉडल द्वारा पहुँच बढ़ाई है और 4 लाख से अधिक युवाओं को स्टार्टअप तथा इनोवेशन के विषय में जागृत किया है।

WEstart : महिलाओं को स्टार्टअप क्षेत्र में सशक्त बनाने वाली महत्वपूर्ण पहल

स्टार्टअप क्षेत्र में महिलाओं के समावेश के लिए शुरू की गई WEstart पहल के तहत 196 महिला संचालित स्टार्टअप्स को सहायता दी गई है, जो कुल सपोर्टेड स्टार्टअप्स का लगभग 30 प्रतिशत है। राज्य में स्टार्टअप तथा इनोवेशन क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए अहमदाबाद में कार्यरत i-Hub के बाद अब आगामी एक वर्ष में वडोदरा, सूरत, राजकोट तथा मेहसाणा में चार नए सेंटर शुरू किए जाएंगे। स्टार्टअप का यह मजबूत इकोसिस्टम 'आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत' के विजन में भी उल्लेखनीय योगदान देगा।

भावनगर मंडल के लोको पायलटों की सतर्कता से 06 सिंहों को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया गया

(जीएनएस)। भावनगर रेलवे मंडल द्वारा सिंहों/वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। मंडल के निर्देशानुसार ट्रेनों का संचालन करने वाले लोको पायलट निर्धारित गति का पालन करते हुए विशेष सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। भावनगर मंडल के लोको पायलटों की सतर्कता एवं वन विभाग के फॉरेस्ट ट्रैकरों के समन्वय से पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 159 सिंहों की जान बचाई जा चुकी है। वहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 81 सिंहों को सुरक्षित बचाया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 21.12.2025 (रविवार) को लोको पायलट श्री अनीश शेख एवं सहायक लोको पायलट श्री फरमान हुसैन ने सासणगीर–कांसियानेश सेक्शन में किलोमीटर संख्या 112/7–112/6 के बीच रेलवे ट्रैक पर 06 सिंहों को देखा। तत्पश्चात उन्होंने ट्रेन संख्या 52955 वेरावल–जूनागढ़ यात्री गाड़ी को तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सुरक्षित रूप से रोक लिया। लोको पायलट द्वारा ट्रेन मैनेजर (गार्ड) श्री विद्यानन्द कुमार को तुरंत सूचना दी गई। वन विभाग के फॉरेस्ट ट्रैकर श्री राणा भाई द्वारा सभी सिंहों को सुरक्षित रूप से रेलवे ट्रैक से हटाया गया। स्थिति सामान्य पाए जाने के उपरांत लोको पायलट को ट्रेन के प्रस्थान की अनुमति दी गई, जिसके बाद ट्रेन को सावधानीपूर्वक गंतव्य की ओर रवाना किया गया। इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर लोको पायलटों द्वारा किए गए इस सराहनीय एवं संवेदनशील कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रशंसा व्यक्त की गई।

घरेलू कलह बना खूनखराबे की वजह, बेटे के हाथों उजड़ा बाप का साया

(जीएनएस)। प्रयागराज। जिले के बारा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की जान ले ली। शनिवार देर रात हुई इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है और रिश्तों की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार पंडित का पूरा गांव निवासी 68 वर्षीय राम बहादुर और उनके बेटे रामबाबू के बीच पशुओं के चारे को लेकर कहासुनी हो गई। मामूली विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बेटे ने नियंत्रण खो दिया। आरोप है कि रामबाबू ने पास में रखी लाठी उठाकर अपने पिता के सिर पर जोरदार वार कर दिया। अचानक हुए हमले से राम बहादुर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े।

परिजनों और ग्रामीणों की मदद से बुजुर्ग को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिता की मौत की खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया और हर कोई इस अमानवीय घटना से स्तब्ध नजर आया।

सूचना मिलते ही बारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि की जा सके। वहीं, आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद ही घटना की मुख्य वजह सामने आई है, हालांकि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पारिवारिक तनाव, गुस्सा और असंयम किस हद तक विनाशकारी हो सकते हैं। जिस पिता ने बेटे को पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी बेटे के हाथों उसकी मौत होना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। गांव में शोक और भय का माहौल है, वहीं लोग यह सवाल भी कर रहे हैं कि छोटी-छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा आखिर कब रिश्तों को लहूलुहान करना बंद करेगा।

अहमदाबाद मंडल के आम्बली रोड स्टेशन पर बनाया जा रहा है "रेल कोच रेस्टोरेंट"

नागरिकों को मिलेगा यात्रा जैसा अनुभव, स्वादिष्ट भोजन और विभिन्न सुविधाएँ

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा आंबली रोड रेलवे स्टेशन पर आधुनिक 'रेल कोच रेस्टोरेंट' का निर्माण किया जा रहा है। इस अनूठी पहल के तहत परिवर्तित रेल कोचों में रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है, जहाँ बैठकर लोग बिना यात्रा किए ही चलती ट्रेन में होने जैसा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे। आंबली रोड स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट अहमदाबाद क्षेत्र का पहला रेस्टोरेंट होगा। पश्चिम रेलवे में बांद्रा टर्मिनस, अंधेरी, बोरीवली, रतलाम तथा राजकोट में रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित किए गए है।

इस रेल कोच रेस्टोरेंट में 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी, जिससे यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों को भी दिन-रात भोजन की सुविधा मिलेगी। अहमदाबाद की जनता यहाँ परिवार और मित्रों के साथ बैठकर विभिन्न व्यंजनों का स्वाद ले सकेगी तथा आकर्षक रेल-थीम वातावरण में सेल्फी और यादगार पलों का आनंद उठा सकेगी। इस रेस्टोरेंट में इनडोर एवं आउटडोर डाइनिंग दोनों विकल्प होंगे। इसके साथ ही पर्याप्त पार्किंग, पार्सल/टेक-अवे सुविधा तथा बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था (फन ज़ोन) भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यह स्थान परिवार-अनुकूल बन सके। यह रेस्टोरेंट हरियाली से युक्त सुखद वातावरण प्रदान करेगा तथा सभी सुरक्षा मानको का ध्यान रखकर बनाया जा रहा है।

आंबली रोड के अतिरिक्त, महेसाणा, साबरमती, भुज एवं गांधीधाम रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में भी 'रेल कोच रेस्टोरेंट' विकसित किए जाने की योजना है।

भारतीय रेलवे के अभिनव दृष्टिकोण के तहत इन संशोधित कोचों में आधुनिक डिजाइन, संलग्न किचन (Attached Kitchens) तथा मल्टी-क्यूज़िन मेनू की सुविधा होगी, ताकि विभिन्न स्वादों की पसंद को पूरा किया जा सके। साथ ही, समग्र अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण-अनुकूल एवं आकर्षक माहौल सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन

(जीएनएस)। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर 21 दिसंबर 2025 को आर्ट ऑफ लिविंग के अनुभवी प्रशिक्षकों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर सामूहिक ध्यान सत्र का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेल कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को मानसिक शांति, सकारात्मक सोच तथा आत्मिक संतुलन की ओर प्रेरित करना था, ताकि वे दैनिक जीवन के तनाव और चुनौतियों का सामना अधिक सहजता एवं आत्मविश्वास के साथ कर सकें। वर्तमान समय में बढ़ते वैश्विक तनाव, कार्यस्थल के दबाव तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए विश्व ध्यान दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दिवस मानवता को एक क्षण ठहरकर स्वयं से जुड़ने, आंतरिक शांति प्राप्त करने तथा सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का संदेश देता है। ध्यान सत्र के दौरान प्रतिभागियों को ध्यान के वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक महत्व के बारे में जानकारी दी गई। नियमित ध्यान से व्यक्ति में भावनात्मक स्थिरता आती है, आध्यात्मिक विकास को बल मिलता है, तनाव में कमी होती है तथा समाज में सामुदायिक जुड़ाव और आपसी सौहार्द बढ़ता है। उपस्थित प्रतिभागियों ने अनुभव किया कि ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र कर नकारात्मक

विचारों से ऊपर उठकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। यह सामूहिक ध्यान सत्र अहमदाबाद मंडल के साबरमती कम्युनिटी सेंटर, विरमगाम कम्युनिटी सेंटर, कांकरिया कम्युनिटी सेंटर तथा गांधीधाम कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में रेल अधिकारियों एवं रेल कर्मचारी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सभी प्रतिभागियों ने शांत वातावरण में ध्यान का अभ्यास किया और मानसिक सुकून का अनुभव किया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के प्रेरणादायी विचारों को भी साझा किया गया कि "ध्यान ही वह माध्यम है जिससे नकारात्मक विचारों से ऊपर उठकर सकारात्मकता स्वतः और स्वाभाविक रूप से आती है।" पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल सभी रेल कर्मचारियों से अपील करता है कि वे अपने दैनिक जीवन में ध्यान को अपनाएं तथा ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता करें, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ-साथ कार्यक्षमता, आपसी समन्वय एवं सामाजिक सद्भाव को भी मजबूती मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का योग तथा ध्यान की प्राचीन परंपरा को स्वस्थ संतुलित समाज के निर्माण के लिए जन आंदोलन बनाने का आह्वान

- महात्मा मंदिर में विश्व ध्यान दिवस का उत्साहपूर्ण उत्सव
- गुजरात राज्य योग बोर्ड के योग कोच व ट्रेनर्स का प्रथम दीक्षांत समारोह संपन्न - मुख्यमंत्री ने प्रमाणपत्र प्रदान किए
- हिमालयन समर्पण मेडिटेशन के पूज्य श्री शिवकृपानंद स्वामीजी के पावन सान्निध्य में सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को योग साधना तथा ध्यान की प्राचीन परंपरा को स्वस्थ व संतुलित समाज निर्माण के लिए जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य को मन की शांति और स्वस्थ एवं निरोगी जीवनशैली के साथ ध्यान तथा योग से ही समाज तथा राष्ट्र निर्माण द्वारा साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता करते हुए गुजरात राज्य योग बोर्ड के कोच एवं योग ट्रेनर्स के प्रथम दीक्षांत समारोह एवं विश्व ध्यान दिवस समारोह को संबोधित किया।

उन्होंने योग ट्रेनर्स को बधाई देते हुए कहा कि योग शारीरिक शक्ति बढ़ाता है तथा ध्यान मन की एकाग्रता बढ़ाता है। योग करने की शक्ति का संचय ध्यान से प्राप्त होने वाली मजबूत निर्णय शक्ति द्वारा ही होता है।

मुख्यमंत्री ने ध्यान को भारत की प्राचीन परंपरा से उपजा हुआ वरदान बताते हुए कहा कि आज के तेज और तनावपूर्ण समय में मानसिक शांति के लिए यह उतना ही प्रासंगिक है।

श्री पटेल ने कहा कि भारत विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाला देश है। उन्होनें गौरवपूर्ण उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग को जो वैश्विक मान्यता दिलाई; उसके परिणामस्वरूप 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री ने योग को स्वास्थ्य रक्षा का परंपरागत सरल भाग बताते हुए नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान से रोग- बीमारी से मुक्त रहने का उपाय सुझाया है।

उन्होंने 'आयुष्यमान भारत' सुविधा की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि 'आयुष्यमान भारत' जैसी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, जिसमें योग के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षा के बावजूद यदि किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके उपचार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 'आयुष्मान भारत' योजना दी गई है ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में योग और ध्यान बिना किसी खर्च या दुष्प्रभाव के एकाग्रता, निर्णय शक्ति और आंतरिक शांति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के करकमलों से योग प्रशिक्षकों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री शीशपालजी राजपूत ने योग बोर्ड की गतिविधियों, उनकी प्रासंगिकता तथा योग के माध्यम से स्वस्थ राज्य से स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में योग प्रशिक्षकों की भूमिका की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी का स्वागत किया।

इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, हिमालयन समर्पण मेडिटेशन के गुजरात प्रांत के पदाधिकारी, योग ट्रेनर्स व बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

कोहरे और कड़ाके की सर्दी ने रेल और हवाई यात्रा को किया प्रभावित: दर्जनों ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

(जीएनएस)। देशभर में ठंड ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और सुबह के समय घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे यात्रियों को ट्रेन और फ्लाइट दोनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कोहरे और ठंड के असर बने रहने की संभावना जताई है, जिसका सीधा असर ट्रेनों और हवाई यात्राओं पर पड़ रहा है।

रेलवे यातायात पर सबसे अधिक असर पड़ा है। कोहरे की वजह से सुबह अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली ट्रेनें अब दोपहर या रात में पहुंच रही हैं। कुछ ट्रेनें 10 से 18 घंटे तक लेट हो रही हैं। इसी दौरान करीब 102 ट्रेनों में देरी हुई और चार ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना पड़ा। प्रभावित ट्रेनों में झेलम एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस विवेक एक्सप्रेस, दिल्ली-सराय रोहिल्ला एसी दूरंतो एक्सप्रेस और श्रीगंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं। कानपुर, इटावा और उन्नाव जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। इटावा रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस और आगरा-लखनऊ इंटरसिटी को रद्द करना पड़ा, जबकि अन्य कई प्रमुख ट्रेनें घंटों की देरी से पहुंचीं। अप लाइन में कैफियत एक्सप्रेस करीब 10 घंटे 40 मिनट, पूर्वा एक्सप्रेस लगभग 2 घंटे 55 मिनट, मरुधर एक्सप्रेस 1 घंटे 15 मिनट, आम्रपाली एक्सप्रेस 1 घंटे 54 मिनट, अवध एक्सप्रेस 1 घंटे 18 मिनट, लालगढ़-प्रयागराज एक्सप्रेस 1 घंटे 14 मिनट और वैशाली एक्सप्रेस करीब 2 घंटे 58 मिनट लेट रही। वहीं लिंक, संगम, मगध, कोटापटना, ऊंचाहार, फरक्का, गोमती, शताब्दी और मुरी एक्सप्रेस भी 1 से 4 घंटे तक लेट हुईं। कालका मेल लगभग डेढ़ घंटे देरी से जंक्शन पर पहुंची।

डाउन लाइन में आम्रपाली एक्सप्रेस करीब दो घंटे, शिकोहाबाद पैसेंजर एक घंटे, ऊंचाहार एक्सप्रेस लगभग 9 घंटे 41 मिनट, वैशाली एक्सप्रेस 1 घंटे 9 मिनट, पूर्वा एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट और कैफियत एक्सप्रेस करीब 7 घंटे 50 मिनट लेट रही। पटनाकोटा, प्रयागराज-लालगढ़ और मरुधर एक्सप्रेस 2 से 4 घंटे, जबकि कालका मेल लगभग 1 घंटे 33 मिनट लेट स्टेशन पर पहुंची।

कानपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ा। वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 4 घंटे, लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस लगभग 6 घंटे लेट रही। डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को करीब 10 घंटे, आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे 45 मिनट और नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल श्रम शक्ति एक्सप्रेस लगभग 6 घंटे देरी से चल रही थी। प्रयागराज एक्सप्रेस 3 घंटे 41 मिनट, आनंद विहार-रीवा एक्सप्रेस 3 घंटे 49 मिनट और ब्रह्मपुत्र मेल लगभग 6 घंटे 22 मिनट की देरी से पहुंची। कालिंदी एक्सप्रेस 9 घंटे 24 मिनट, भृगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 घंटे, विक्रमशिला एक्सप्रेस 3 घंटे 33 मिनट, पूर्वा एक्सप्रेस 4 घंटे 26 मिनट और महाबोधि एक्सप्रेस 5 घंटे 7 मिनट लेट हुई। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 6 घंटे और नई दिल्ली-तेजस राजधानी एक्सप्रेस लगभग 2 घंटे 43 मिनट देरी से चली। एलटीटी-कानपुर सेंट्रल स्पेशल करीब 18 घंटे, बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल लगभग 16 घंटे और एलटीटी-सूबेदारगंज स्पेशल करीब 14 घंटे लेट रही। दरभंगा स्पेशल भी लगभग 5 घंटे की देरी से कानपुर पहुंची। उन्नाव रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनें देर से पहुंचने की वजह से यात्री परेशान हुए। वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे 20 मिनट, शताब्दी एक्सप्रेस करीब एक घंटे, झांसी पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे और गोमती एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट लेट रही। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कानपुर एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई। कई फ्लाइट्स निर्धारित समय से लेट पहुंचीं, जिससे यात्री एयरपोर्ट पर लंबी लाइन और इंतजार का सामना कर रहे हैं। मौसम और कोहरे का यह असर आने वाले दिनों में भी बना रहने की संभावना है, इसलिए यात्रियों को अपने सफर की योजना में अतिरिक्त समय शामिल करने की जरूरत है। देशभर में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। ट्रेन और फ्लाइट्स की लेट होने की वजह से यात्रियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रेलवे प्रशासन और हवाई अड्डा स्टाफ हरसंभव प्रयास कर रहे हैं कि यात्रियों की परेशानी कम से कम हो। लेकिन मौसम के तेज प्रभाव के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों और उड़ानों में अभी और देरी होने की संभावना है।

नैनीताल में प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या की साजिश रची, 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

(जीएनएस)। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में प्रेम और पैसों के विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। साल 2020 में भीमताल क्षेत्र में हुई इस हत्या की कहानी अब पांच साल बाद कोर्ट के फैसले के साथ सामने आई है। अमरीन जहां नाम की महिला ने अपने प्रेमी नाजिम अली की हत्या कर दी थी, क्योंकि नाजिम ने शादी के बाद किसी और महिला से विवाह करने के बाद अपनी पूर्व प्रेमिका को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था। इससे नाराज होकर अमरीन ने राधेश्याम शुक्ला के साथ मिलकर नाजिम की हत्या की योजना बनाई।

जांच और सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि अमरीन और नाजिम पहले से ही एक संबंध में थे। लेकिन नाजिम की दूसरी शादी के बाद उसने अमरीन को खर्चा देना बंद कर दिया। नाराज अमरीन ने इस बात को व्यक्तिगत अपमान और आर्थिक नुकसान समझा और राधेश्याम शुक्ला की मदद से हत्या की योजना बनाई। कोर्ट ने इस मामले में अमरीन जहां और राधेश्याम शुक्ला को हत्या और आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया है। साथ ही राधेश्याम शुक्ला को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी माना गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की कोर्ट सोमवार, 22 दिसंबर को दोषियों को सजा सुनाएगी।

घटना की समयरेखा भी बेहद chilling है। जनवरी 2020 में अमरीन ने नाजिम को घूमने के बहाने भीमताल ले गई। काठगोदाम-भीमताल मार्ग पर चंदा देवी मंदिर के पास हेयरपिन मोड़ के नजदीक राधेश्याम शुक्ला ने 315 बोर के तमंचे से नाजिम को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद अमरीन ने नाजिम के मोबाइल से उसके भाई वाजिद अली को कॉल करके झूठी जानकारी दी कि नाजिम का एक्सीडेंट हो गया है। उसी शाम थाना भीमताल में हत्या का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने घटनास्थल और सबूतों की पूरी जांच की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि हत्या के समय दोनों आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे। मौके से मिला कारतूस और खून के नमूने भी मृतक के साथ मेल खा गए।

यह मामला नैनीताल जिले में प्रेम, पैसों और झूठे आरोपों के कारण हत्या की गंभीरता को उजागर करता है। पांच साल की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला समाज में यह संदेश देता है कि हत्या और आपराधिक साजिश को कानून नजरअंदाज नहीं करता। इस घटना ने स्थानीय लोगों में डर और चिंता बढ़ा दी थी और अब कोर्ट के फैसले से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी।

यदि आप चाहें तो मैं इसे और लंबा और विस्तृत करके अखबार के लिए 2,500–3,000 शब्दों में एक पूर्ण रिपोर्ट तैयार कर दूँ, जिसमें घटना की पृष्ठभूमि, आरोपी और पीड़ित का विवरण, पुलिस जांच, कोर्ट की प्रक्रिया और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया जाए। क्या मैं इसे तैयार कर दूँ?

बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में नेपाल में प्रदर्शन, मुस्लिम समाज ने भी जताई निंदा

(जीएनएस)। काठमांडू। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में झूठे आरोप के तहत एक हिंदू युवक की पिटाई कर हत्या और शव को जलाने की घटना के विरोध में नेपाल के वीरगंज में हिंदू युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बांग्लादेश सरकार की आलोचना की। युवाओं ने "हिंदुओं की हत्या नहीं चलेगी" और "बांग्लादेशी मुसलमान मुर्दाबाद" जैसे नारे लगाते हुए वीरगंज नगर का परिक्रमा किया और अंत में घंटाघर पहुंचकर बांग्लादेश के झंडे अंकित चित्र को आग लगा विरोध जताया। प्रदर्शन में हिंदू समुदाय के नेता विकास साह ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू बार-बार उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होते रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। साह ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। नेपाल मुस्लिम समाज संघ, पर्सा ने भी इस अमानवीय घटना की कड़ी निंदा की।

संघ के अध्यक्ष महबूब अली (शेरू) ने कहा कि अल्पसंख्यक हिंदू युवक की हत्या ने समाज को गहरे दुख और चिंता में डाल दिया है। उन्होंने मानवता, सह-अस्तित्व और धार्मिक सहिष्णुता पर इस प्रकार की हिंसा को गंभीर चुनौती बताया। मुस्लिम संघ ने विश्वभर में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भाईचारा, प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर होने वाली हिंसा सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है। संघ ने नेपाल को हमेशा धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता का उदाहरण बताते हुए पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। यह प्रदर्शन और मुस्लिम समाज की निंदा दोनों ही इस बात का संदेश देते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर समाज की जिम्मेदारी है, और हिंसा की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वेदांता का डिमर्जर: शेयरधारकों को लाभांश जारी रखने का आश्वासन, 2030 तक उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य

(जीएनएस)। मुंबई। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने निवेशकों और शेयरधारकों को आश्वस्त किया है कि आगामी डिमर्जर और विस्तार योजनाओं के बावजूद वेदांता की कंपनियां नियमित लाभांश भुगतान जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, "लाभांश मेरे खून में है। चाहे कुछ भी हो, हमारी कंपनियां हमेशा लाभांश देंगी।"

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बीते मंगलवार को वेदांता के डिमर्जर की योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत समूह के धातु, तेल और गैस, पावर और अन्य कारोबार को अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित किया जाएगा। डिमर्जर के बाद बेस मेटल्स कारोबार वेदांता लिमिटेड में रहेगा, जबकि वेदांता एल्युमिनियम, तलवंडी साबो पावर, वेदांता स्टील एंड आयरन और मालको एनर्जी स्वतंत्र कंपनियों के रूप में काम करेंगी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी ने पहला अंतरिम लाभांश सात रुपये प्रति शेयर और दूसरा अंतरिम लाभांश 16 रुपये प्रति शेयर घोषित किया है। पिछले वर्ष कुल लाभांश लगभग 46 रुपये प्रति शेयर रहा। अग्रवाल ने कहा कि यह परंपरा अब भी जारी रहेगी और हर वेदांता शेयरधारक को लाभांश मिलेगा।

भारी निवेश और उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य

अग्रवाल ने विस्तार योजनाओं का विवरण देते हुए बताया कि अगले 4-5 वर्षों में वेदांता 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। इसमें तेल और गैस तथा एल्युमिनियम में 4-4 बिलियन डॉलर, जिंक और सिल्वर में 2 बिलियन डॉलर, पावर में 2.5 बिलियन डॉलर और शेष निवेश आयरन, स्टील और अन्य कारोबारों में किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक उत्पादन दोगुना करना है। सिल्वर उत्पादन 1500 टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है, सीसा उत्पादन 4 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन, जिंक उत्पादन 1.13 मिलियन टन से बढ़ाकर 2 मिलियन टन और एल्युमिनियम क्षमता 3 मिलियन टन से दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तेल और गैस उत्पादन को 3 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 5 लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाने की योजना है। आयरन और स्टील कारोबार हरे स्टील पर केंद्रित रहेगा, जबकि पावर कारोबार में 25,000 मेगावॉट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 15,000 मेगावॉट थर्मल और 5,000 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा शामिल है।

स्वतंत्र बोर्ड और शेयर वितरण

डिमर्जर के बाद प्रत्येक कंपनी का बोर्ड स्वतंत्र रूप से काम करेगा और प्रमोटर्स 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हुए रोज़मर्रा के संचालन में शामिल नहीं होंगे। अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक कारोबार को स्वतंत्र और शुद्ध-खेल कंपनी के रूप में विकसित करना वेदांता की रणनीति का हिस्सा है। डिमर्जर के बाद प्रत्येक वेदांता शेयरधारक को हर डीमरज्ड कंपनी का एक शेयर मिलेगा, जिससे निवेशकों को समूह के सभी कारोबार में हिस्सेदारी मिलेगी।

इस कदम से वेदांता न केवल अपने निवेशकों को भरोसा दे रही है, बल्कि भविष्य में उत्पादन और लाभांश वृद्धि के माध्यम से कंपनी को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की तैयारी कर रही है।

झारखंड के रामगढ़ में सरेआम ज्वेलरी शॉप लूट, करोड़ों के गहने और नकदी लेकर पांच बदमाश फरार, इलाके में हड़कंप

(जीएनएस)। झारखंड के रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप में सरेआम लूटपाट की घटना को अंजाम देकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। शनिवार की रात हुई इस घटनाक्रम में पांच नकाबपोश और हथियारों से लैस बदमाश विजय ज्वेलर्स नामक दुकान में घुस गए। जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने पहले दुकान में मौजूद मालिक और कर्मचारियों को बंदूक के बल पर डराया और फिर डेढ़ किलो सोने, करीब एक क्विंटल चांदी के आभूषण तथा नगदी लूटकर फरार हो गए। इस लूट की कुल अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये बताई जा रही है। घटना की पूरी योजना को देखकर लगता है कि यह अत्यंत संगठित और सोची-समझी कार्रवाई थी। बदमाश पहले ग्राहक बनकर दुकान में आए और जैसे ही अंदर पहुंचे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए ताकि उनकी पहचान रिकॉर्ड न हो। इसके बाद, उन्होंने महज दस मिनट में पूरे स्टॉक को कब्जे में लेकर बाहर निकलने की रणनीति अपनाई। लूट के बाद आरोपी पैदल ही दुकान से दूर चले गए, जहां उनकी गाड़ी पहले से इंतजार कर रही थी, और उसमें बैठकर उन्होंने आसानी से फरार हो गए।

भुरकुंडा थाना पुलिस ने जैसे ही लूट की सूचना पाई, तुरंत छानबीन और कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़कर लूट का सारा माल बरामद कर लिया जाएगा। स्थानीय लोग और व्यापारी इस घटना से भयभीत हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। इस लूटपाट ने न केवल स्थानीय व्यापारियों में डर पैदा किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के संगठित अपराध रोकने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ाई जाएगी और नागरिकों को सतर्क रहने के लिए भी सतत संदेश दिया जाएगा। रामगढ़ की यह घटना झारखंड में बढ़ते अपराधों की ओर एक चेतावनी है, जहां लूट, डकैती और हिंसा आम होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इन घटनाओं को रोकने के लिए तकनीकी साधनों और सामुदायिक सहयोग का इस्तेमाल करना होगा। लूट के इस मामले ने साबित कर दिया कि अपराधी पूरी तैयारी और योजनाबद्ध तरीके से बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और इसे रोकने के लिए समय रहते कदम उठाना आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ पुलिस का सक्रिय होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समुदाय और व्यापारियों की सतर्कता और सहयोग भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द ही जांच पूरी की जाएगी और अपराधियों को कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।

ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास का नाम बदला, बंगबंधु हॉल अब 'शहीद शरीफ उस्मान हादी' के नाम से जाना जाएगा

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश की राजनीति और शैक्षणिक जगत में एक बड़ा और प्रतीकात्मक बदलाव सामने आया है। अंतरिम यूनुस सरकार के कार्यकाल में ढाका विश्वविद्यालय ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने देश की सियासी बहस को और तेज कर दिया है। विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक 'बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल' का नाम बदलकर अब 'शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल' कर दिया गया है। यह निर्णय हाल ही में मारे गए छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की स्मृति में लिया गया है, जिन्हें जुलाई आंदोलन का प्रमुख चेहरा माना जाता है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शरीफ उस्मान हादी वही छात्र नेता थे, जिनकी सक्रिय भूमिका ने पिछले वर्ष शेख हसीना सरकार के खिलाफ चले जनआंदोलन को नई दिशा दी थी। जुलाई आंदोलन ने बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ लाया और अंततः शेख हसीना सरकार के पतन का रास्ता साफ हुआ। हादी की लोकप्रियता और प्रभाव खासतौर पर युवाओं और विश्वविद्यालय परिसरों में काफी गहरा था।

12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान

हादी पर जानलेवा हमला किया गया। नकाबपोश हमलावरों ने बेहद नजदीक से उनके सिर में गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत नाजुक होने के कारण उन्हें तत्काल इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद छह दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु की खबर सामने आते ही पूरे बांग्लादेश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जगह-जगह हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं और सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया।

हादी की मौत के बाद ढाका यूनिवर्सिटी के विभिन्न छात्र संगठनों ने खुलकर उनकी शहादत को सम्मान देने की मांग उठाई। छात्रों का कहना था कि जिस विश्वविद्यालय से हादी की राजनीतिक और सामाजिक चेतना को पहचान मिली, वहां उनकी याद को स्थायी रूप से जीवित रखा जाना चाहिए। इसी मांग के तहत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आया, जिसे लेकर देशभर में बहस भी छिड़ गई।

शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे विश्वविद्यालय परिसर में इस फैसले को अमल में लाया गया। क्रेन की मदद से हॉल के मुख्य द्वार पर लगे पुराने नेमप्लेट को हटाया गया और उसकी जगह नया बोर्ड लगाया गया, जिस पर बड़े अक्षरों में 'शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल' लिखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे और उन्होंने हादी के समर्थन में नारे लगाए। माहौल भावुक भी था और राजनीतिक संदेश से भरा भी।

इस नाम परिवर्तन को जहां एक वर्ग शहीद छात्र नेता को सम्मान देने की ऐतिहासिक पहल बता रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत से दूरी बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अंतरिम सरकार के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि देश में सत्ता परिवर्तन के बाद न केवल राजनीतिक समीकरण बदले हैं, बल्कि प्रतीकों और स्मृतियों को लेकर भी नई दिशा तय की जा रही है। ढाका यूनिवर्सिटी का यह कदम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति और समाज में और गहरे असर छोड़ सकता है।

बंगाल की राजनीति में तीसरे मोर्चे की आहट, टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर का 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा करने का दावा करते हुए तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि वह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाकर राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि सत्ता की चाबी तय करने वाले "किंगमेकर" की भूमिका में देखते हैं। उनके इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है और सत्तारूढ़ टीएमसी से लेकर विपक्षी दलों तक नई रणनीतियों पर मंथन शुरू हो गया है।

हुमायूं कबीर ने बताया कि सोमवार को मुर्शिदाबाद में उनकी नई पार्टी का औपचारिक गठन किया जाएगा। पार्टी के नाम का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग में टेबल समेत तीन चुनाव चिन्हों के लिए आवेदन कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह चुनावी मैदान में पूरी तैयारी और गंभीरता के साथ उतरने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राज्य की हर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारेगी और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी।

कबीर ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ टीएमसी से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी होगी। उनके अनुसार बंगाल की जनता अब दो ध्रुवों की राजनीति से ऊब चुकी है और एक ऐसे विकल्प की तलाश में है, जो जमीनी मुद्दों पर बात करे और सत्ता के दंभ से दूर रहे। इसी भरोसे के साथ वह खुद को जनता की आवाज बताकर मैदान में उतर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह संकेत भी दिए कि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस, सीपीआई(एम) और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के साथ भविष्य में किसी तरह के तालमेल या गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

नई पार्टी के औपचारिक ऐलान से पहले ही मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। जिले के कई इलाकों में उनके समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और मिर्जापुर इलाके में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। कबीर के समर्थकों का दावा है कि इस कार्यक्रम में करीब चार लाख लोगों की भीड़ जुट सकती है, जो उनकी राजनीतिक ताकत और जनाधार को दिखाने के लिए काफी माना जा रहा है। यह भी साफ है कि मुर्शिदाबाद को हुमायूं कबीर अपनी राजनीति का मजबूत गढ़ बनाने की कोशिश में जुट गए हैं।

हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से कम से कम 10 सीटों पर उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी। फिलहाल जिले की 20 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कबीर का कहना है कि जमीनी हकीकत तेजी से बदल रही है और जनता अब नए चेहरे और नई सोच को मौका देना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ सीटें जीतना नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति की दिशा बदलना है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में हुमायूं कबीर का यह ऐलान सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। जहां टीएमसी के लिए यह एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है, वहीं बीजेपी और अन्य विपक्षी दल भी इस नए घटनाक्रम को गंभीरता से देख रहे हैं। हुमायूं कबीर की नई पार्टी वास्तव में कितना असर डाल पाएगी, यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि उनके इस कदम ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस और नई हलचल जरूर पैदा कर दी है।